Demand to take effective steps for early disposal of large number of pending cases in the courts of the country

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश): महोदय, यह पुरानी कहावत है कि "Justice delayed is justice denied." देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमे हमारी न्याय व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। त्वरित न्याय का न हो पाना भी प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार का एक कारण है। जहां देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या लाखों में है, वहीं अधीनस्थ न्यायालयों में यह संख्या करोड़ों में है। वादी या अपीलकर्ता अपनी बारी का इंतजार करते और तारीख पर तारीख लेते-लेते काल के गाल में समा जाते हैं और यह काम उनके पुत्र-पुत्रियों या कभी-कभी तो पौत्र-पौत्रियों को करना पड़ता है। भारत के पूर्व रेल मंत्री - स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र की हत्या हुए लगभग 40 वर्ष का समय हो चुका है और मामला अभी भी दिल्ली की एक कोर्ट में लंबित है। ऐसे ही न जाने कितने मुकदमे हैं, जो दशकों से अदालतों में लटके हुए हैं। दूसरी ओर अदालतों में न्यायाधीशों के सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। मेरे गृह राज्य - उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 160 है, जब कि इनमें से मात्र 62 न्यायाधीश कार्यरत हैं, अर्थात् लगभग 65 प्रतिशत पद खाली हैं। ऐसे में लंबित मुकदमों के निपटान की उम्मीद कैसे की जा सकती है? न्यायालयों में खाली पदों को भरने का क्या प्रयास हो रहा है? क्या न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु (Retirement Age) को 62 से 65 वर्ष करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो इस विषय में शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है, जिससे देश के गरीब लोग शीघ्र न्याय पा सकें। इसके अतिरिक्त न्यायालयों में खाली पद भी शीघ्रता से भरे जाने चाहिए।

Demand to grant presidential assent to the Karnataka Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle Bill

SHRI M. RAMA JOIS (Karnataka): Sir, Karnataka Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle Bill passed by the Karnataka Legislature was sent by the Governor of Karnataka to the President of India having reserved the Bill for the assent of the President and was sent to the President in the month of May, 2010.

In view of the inordinate delay in giving the assent, 250 citizens of Karnataka commenced Pada Yatra from Hubli in Karnataka to Delhi on 17th January, 2011 and had reached Delhi on 24th March, 2011, and held demonstration at Jantar Mantar urging the President to give assent to the Bill. Later, they came to know from news item published in Garden City Patrika that the Bill has not reached the Office of the President and its whereabouts are not known. Concerned Ministry of the Government of India not sending the Bill for the consideration of the President though it is more than one year, is highly regrettable.